

स्वास्थ्य सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा तक . एक नीतिगत विश्लेषण

डॉ सुमन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज

शेख सराय फेज-2ए नई दिल्ली

लेख के मुख्य शब्द

सार्वभौमिक किफायतीए जीवनशैलीए पहचानकर्ताए सूचीबद्धए धोखाधड़ीए प्रत्यारोपणए भागीदारीए डायलिसिसए विश्लेषणए अपेक्षाकृतए सहमतए परिभाषित।

सार

स्वास्थ्य सेवा में निवेश समुदायों को अधिक लचीला सक्षम और उत्पादक बनाता है। कमजोर परिवारों सहित सभी लोगों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना जिससे वे स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी सकें। भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्ति ऊपर की ओर करता है आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 के लागू होने से भारत सरकार किफायती सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही है जिससे लोग अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आनंद ले सकें और विकसित भारत का निर्माण संभव हो सकें। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना है जिसमें करोड़ों कमजोर भारतीय परिवारों का नामांकन किया गया है।

1^{वां} उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति²⁰¹⁷ भारत में बदलती स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करती है क्योंकि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है सामाजिक-आर्थिक स्थितियां विकसित हो रही हैं और रोग पैटर्न बदल रहे हैं जैसे कि गैर-संचारी रोगों जैसे जीवनशैली रोगों का पारंपरिक संक्रामक रोग। आयुष्मान भारत योजना इस नीति के अनुरूप एक स्तंभ है जो विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समान स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक स्वास्थ्य पहल है। जिसके तहत कम आय वाले और कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करना है। चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्षभर में 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा खर्च की सीमा

निर्धारित है। आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए भारत सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिसमें लगभग 12 करोड़ से अधिक कमजोर और कम आय वाले परिवार जिसमें लगभग 55 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हैं।

2^o सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

यहां तक की आय की सीमा के परे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक कवरेज का विस्तार किया गया जिसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा खर्च का अतिरिक्त वार्षिक टॉप-अप शामिल है। जिसका भारत भर में सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार उपलब्ध है। योजना हेतु पात्र प्रत्येक नागरिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचानकर्ता बनवा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा कर सकते हैं। यह 14 डिजिट नंबर जो भारत के डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिभागी के रूप में नागरिक की विशिष्ट पहचान करता है। इसमें अस्पताल, क्लीनिक, प्रयोगशाला, नैदानिक केंद्र, फार्मसी आदि जैसी सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य हमारे देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करना है। स्वास्थ्य तकनीक कंपनियों के साथ जुड़ाव स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह साझेदारी स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने में भी मदद करेगी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मोटे तौर पर देश के निचले 50% लोग इस योजना के लिए योग्य हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है और एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार और राज्यों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। हालाँकि राज्य सरकारों के अलग-अलग विचारों के कारण यह योजना अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं की जा सकी है।

सितंबर 2024 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश की वरिष्ठ आबादी को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि या पेंशन या बचत से आय कुछ भी हो। यह भारत में बुजुर्ग देखभाल की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि पहले कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर मिलेगा जिसे उन्हें अन्य परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सरकारी चिकित्सा बीमा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी कवर किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने निजी बीमा प्रदाताओं से बीमा योजनाएं ली थीं वे भी कवर किए जाएंगे। योजना पोर्टेबल है और एक लाभार्थी अपने राज्य के बाहर और देश में कहीं भी किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत भारत में सार्वजनिक प्रणाली

में आवश्यक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बीमा-आधारित प्रणाली की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया गया है।

निजी क्षेत्र की तुलना में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पुरानी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा एक नए प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण के रूप में उभरा जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य व्यय के विनाशकारी आउट ऑफ पॉकेट खर्च को रोकने में मदद मिली है। इस मॉडल के माध्यम से राज्य निजी बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करेगा जो पात्र व्यक्तियों को किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्थान में मुफ्त उपचार प्राप्त करने की अनुमति देगा जो च्छ.श्र।ल योजना में शामिल हो गया है। भारत सरकार ने माना कि व्यक्तिगत आउट ऑफ पॉकेट व्यय लोगों को गरीबी में धकेल रहा है और सरकारी अस्पतालों में उपचार अधिकतम खर्च के पश्चात भी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहा था। आयुष्मान योजना में सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा का विकल्प गरीब व्यक्तियों को अतिरिक्त खर्चों के बिना निजी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। आयुष्मान योजना के कारण सरकारी अस्पतालों का राजस्व बढ़ा है मरीजों को बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं। अपनी शुरुआत के बाद से इस योजना ने 116⁹⁹ मिलियन से अधिक मरीजों द्वारा अस्पताल में भर्ती होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह योजना भारत की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लगभग 40% को लक्षित करती है और इसमें हजारों सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पताल शामिल हैं।

सितंबर 2018 में लॉन्च के तुरंत बाद कुछ राज्यों और क्षेत्रों ने आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया। जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने शुरू में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास अपने-अपने राज्य के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम थे। ये कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और तमिलनाडु में पहले से ही राज्य स्वास्थ्य योजनाएँ अच्छी तरह से काम कर रही थीं। लेकिन बाद में कुछ सुधारों को अपनाकर ये राज्य अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गए। इसी तरह केरल अपने स्वयं के स्वास्थ्य कार्यक्रम के बावजूद नवंबर 2019 में आयुष्मान भारत योजना का उपयोग शुरू करने के लिए सहमत हुआ। पश्चिम बंगाल शुरू में कार्यक्रम में शामिल हुआ लेकिन फिर अपने क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना के पक्ष में बाहर हो गया। मई 2020 में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला लिया। तेलंगाना भी मई 2021 में आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया। लेकिन ओडिशा योजना में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि 2017 में शुरू की गई बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना आयुष्मान भारत योजना की तुलना में अधिक लाभकारी बताई गई लेकिन अप्रैल 2025 में ओडिशा इस योजना में शामिल हो गया। दिल्ली में इस योजना को औपचारिक रूप से अप्रैल 2025 में लागू किया गया। भारतीय जनता की भागीदारी से मई 2020 तक ही

आयुष्मान भारत योजना में एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका था। जिसमें इस योजना के तहत रुपए 13,412 करोड़ के मूल्य के साथ 1 करोड़ से अधिक मरीजों को उपचार प्रदान किया गया।

आज देशभर में इस योजना के तहत सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या 24,432 से अधिक है। आयुष्मान भारत योजना ने नवंबर 2019 में कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम के साथ एक विशेष सहयोग की घोषणा की और जून 2020 में इस कार्यक्रम ने 15 अस्पतालों में उस बीमा के साथ 120,000 श्रमिकों को कवर करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट में प्रवेश किया। हालाँकि भारत में अभी भी कुछ बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं चुनौतियां हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम डॉक्टर, धन की कमी, संक्रामक रोगों के अधिक मरीज और स्वास्थ्य योजनाओं में अपेक्षाकृत कम केंद्रीय सरकार के निवेश के साथ एक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु काम राष्ट्रीय बजट इत्यादि शामिल है। कुछ समस्याएं स्वास्थ्य विभाग के बाहर हैं जैसे शहरी विकास और परिवहन जबकि सरकारी हस्पतालो के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद भी कुछ निजी कॉर्पोरेट अस्पताल सरकारी सब्सिडी के साथ भी सरकार की कम कीमत पर अपनी विशेष सेवाएं देने में असमर्थता जताते हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा लाभों के दुरुपयोग के चलते अधिकारियों को गैर-अनुपालन वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है जिसमें इन अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित करना या उन्हें डी-इम्पैनल करना शामिल है। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई न केवल योजना के संसाधनों पर दबाव डालती हैं बल्कि रोगी के विश्वास और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भरोसे से भी समझौता करती हैं। उत्तराखंड राज्य में ही इस तरह के कम से कम 697 फर्जी मामले पाए गए जहां इस योजना के तहत धोखाधड़ी के लिए अस्पतालों पर 1,02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। धोखाधड़ी को रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद भी इस योजना को लाभार्थी तक पहुंचने तथा सफल इम्प्लीमेंटेशन में अनेक बाधाएं विद्यमान हैं जिनका निराकरण आवश्यक रूप से किया जा रहा है इसके साथ साथ बेईमान निजी संस्थाओं पर भी सरकारी सिकंजा कसा जा रहा है।

3rd आयुष्मान भारत योजना का बढ़ता हुआ दायरा

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है जिसका विस्तार करते हुए भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा केंद्रीय पुलिस संगठनों के लगभग 30 लाख सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके साथ-साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ उनके अधिकतम चिकित्सा खर्च की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है जिससे यह योजना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवारत कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्रीय पुलिस संगठनों के सभी बड़े अस्पताल आयुष्मान भारत हॉस्पिटल के रूप में घोषित किए गए हैं जहां पर केंद्रीय पुलिस संगठनों के कर्मियों व

उनके परिवार सदस्यों के अलावा कोई भी सामान्य व्यक्ति समस्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।

4th निष्कर्ष

निसंदेह इस योजना का दायरा और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है तथा वर्तमान में बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए इसके खर्च की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो भी इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली विसंगतियों को यदि दूर कर दिया जाए तो यह योजना भारतीय इतिहास में स्वस्थ क्षेत्र में सबसे बेहतरीन योजनाओं में शामिल है। देश में इस तरह की स्वास्थ्य योजना को लाया जाना अपने आप में एक बहुत ही अनूठी पहल है जो की 2047 में भारत के विकसित देश बनने में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का विकास होता है और जिस देश की जनता स्वस्थ है उस देश का विकास निश्चित है। कुछ राजनीतिक दूर्वाग्रहों से बचते हुए बेईमान और देशद्रोही लोगों तथा संस्थानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस योजना को देश के ज्यादातर हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए ताकि इस योजना का लाभ पूरे भारतवर्ष के नागरिक को प्राप्त हो सके और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना में शामिल हो पाए।

संदर्भ.

- 1st |लनीउंद ठीतंजरु बवउचसमजम हनपकम जव च्द.श्र।ल्ए |लनीउंद बंतक – भ्वेचपजंस इमदमपिजे इलैनदपजं लनचजं आयुष्मान भारत: च्द.श्र।ल्ए आयुष्मान कार्ड और अस्पताल से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में पूरी जानकारी सुनीता गुप्ता द्वारा
- 2nd |लनीउंद ठीतंजरु इनज जूज बवेजठ ठल |लनी त्र आयुष्मान भारतए लेकिन किस कीमत पर आयुष राज द्वारा
- 3rd ठमेज चतंबजपबम ठववासमज वछिंजपवदंस भंसजी |नजीवतपजल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस बुकलेट
- 4th |लनीउंद बवअमत बकत चकदिवजम वी।प्डैए छमू कमसीप |प्डैए नई दिल्ली का आयुष्मान कवर से जुड़ा चक़ि नोट
- 5th ैवच वी।ककस कळ ब।च्चेए छैळ – |त ब।च्चेए छैळ और |त के एडिशनल कळ कीैळ